सरकारी ग्रांटों को हड़प गयीं शहर की संस्थाएं

पड़ताल : किसी भी संस्था ने उपयोगिता प्रमाणत्र जमा नहीं कराया, एक ने कराया तो कई मामले खुले

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: सरकारी ग्रांट के रूप में मिले जनता के पैसे को हड़पने वाले तमाम धार्मिक, सामाजिक संगठन अभी तक हरियाणा सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (उपयोगिता प्रमाणपत्र) तक नहीं दे सके। यानी मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों से प्राप्त सरकारी ग्रांट को इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं को दस्तावेज सरकार को देने होते हैं कि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया था। हाल ही में मजदूर मोर्चा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधायक सीमा त्रिखा द्वारा फरीदाबाद के धार्मिक और राजनीतिक संगठनों, कथित गरीबों यानी व्यक्तिगत लोगों को दी गई ग्रांट की सूची छापी थी। इसके बाद हमने यह पड़ताल की कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ। इसके लिए आरटीआई का भी सहारा लिया गया। जनता और सरकार के इस पैसे की बंदरबांट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए फरीदाबाद का जिला प्रशासन और उसके अफसर जिम्मेदार है, जिसके जरिए यह पैसा इन संगठनों को पहुंचा। जिला प्रशासन के अफसरों को इस पैसे पर नजर रखनी चाहिए थी और समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र मांग लेना चाहिए था, लेकिन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे इन अफसरों की नीयत खुद खराब रहती है।

इस ग्रांट पर नजर डालें

मुख्यमंत्री खट्टर ने 19 जनवरी 2018 को विजय राम लीला कमेटी एनआईटी मार्केट नंबर 1 को धर्मशाला बनाने के लिए 11 लाख रुपये की सरकारी ग्रांट (202-बीएपी-1(3)17/301) दी।

मुख्यमंत्री ने श्रीराम धर्मार्थ चेरिटेबल सोसाइटी को 23 मार्च 2018 को 11 लाख रुपये की सरकारी ग्रांट (1196-बीएपी-1(3)17/1269) मशीन/उपकरण खरीदने के लिए दिए ताकि श्रीराम अस्पताल में गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज हो सके।

मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी 2018 को फरीदाबाद धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को जनता के लिए मल्टीपरपज हॉल बनाने के लिए 20 लाख रुपये की सरकारी ग्रांट (202-बीएपी-1(3)17/301) जारी की। गौर से पढ़िए और देखिए मुख्यमंत्री एक ही दिन में फरीदाबाद की दो संस्थाओं को जनता के 31 लाख रुपये लुटा रहा है।

बडखल क्षेत्र की भाजपा विधायक सीमा त्रिखा फरीदाबाद धार्मिक और सामाजिक संगठन, मालवीय वाटिका, दशहरा मैदान फरीदाबाद को 31 जुलाई 2017 में ही 5 लाख रुपये (2506-बीएपी-1(5)17/2539) सामुदायिक भवन बनाने के लिए दे चुकी होती हैं।

विधायक सीमा त्रिखा 11 दिसम्बर 2015 को विजय राम लीला कमेटी को धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 11 लाख रुपये की सरकारी ग्रांट (3046-बीएपी-1(5)15/7408) दे चुकी हैं।

तथ्य खुद बोल रहे हैं

विजय रामलीला कमेटी को विधायक सीमा त्रिखा 2015 में धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 11 लाख रुपये की सरकारी ग्रांट दे चुकी होती हैं लेकिन गौर से देखिए मुख्यमंत्री खट्टर इसी विजय राम लीला कमेटी को 11 लाख रुपये धर्मशाला बनाने के लिए जारी कर रहा है। यानी बिना धर्मशाला बने जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा पहले दे दिया गया। आखिर ये क्या गोरखधंधा है।

हमारी पड़ताल बता रही है कि विजय रामलीला कमेटी ने आज तक उपयोगिता प्रमाणपत्र हरियाणा सरकार और फरीदाबाद जिला प्रशासन को नहीं दिया है। क्या यह माना जाए कि कमेटी के पदाधिकारियों ने 22 लाख रुपये डकार लिए। यह भी सवाल है कि विजय राम लीला कमेटी में एक हॉल तो जरूर बना हुआ है, जहां तमाम धार्मिक

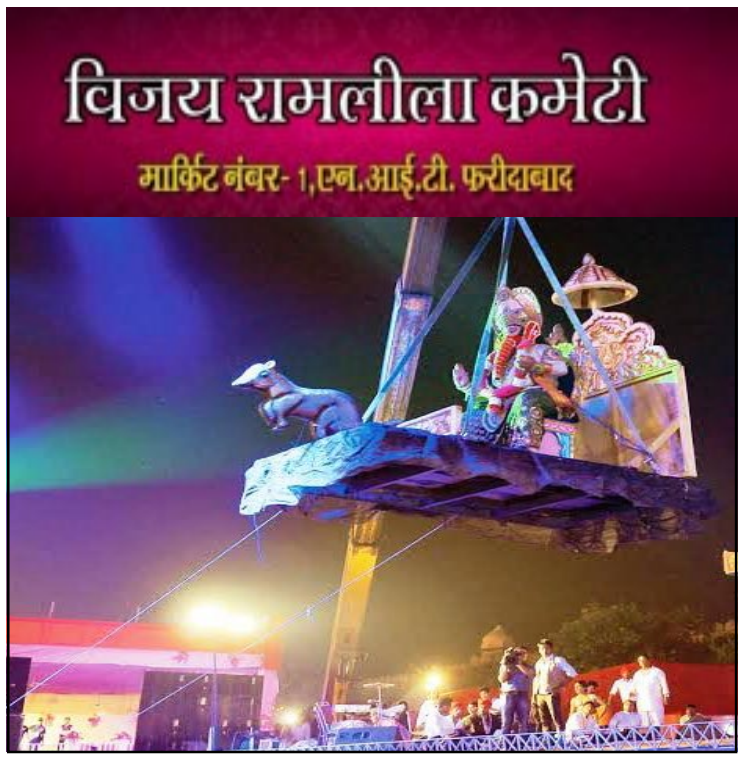

आयोजन होते हैं लेकिन वहां धर्मशाला कहां बनी हुई है। धर्मशाला से आशय है कि वहां आकर लोग ठहरते हों लेकिन विजय रामलीला कमेटी में किसी तरह की धर्मशाला नहीं है।

विजय रामलीला कमेटी ने तमाम अवैध निर्माण सरकारी जमीन यानी एमसीएफ की जमीन पर किए हैं। उन्होंने मार्केट नं. 1 में कई अवैध दुकानें बना दी हैं, जिनका किराया वर्षों से ले रहे हैं। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीएफ विजय रामलीला कमेटी को अवैध निर्माण पर नोटिस जारी कर चुका है। इन अवैध निर्माणों को जब भी तोड़ने की कोशिश एमसीएफ ने करी, उस समय डीसी रहे यशपाल यादव ने तोड़फोड़ रुकवा दी। अब यशपाल यादव खुद नगर निगम कमिश्नर हैं, देखना है कि विजय रामलीला कमेटी का अवैध निर्माण कब तक खड़ा रहता है।

फरीदाबाद सामाजिक धार्मिक संगठन को भी मुख्यमंत्री खट्टर और विधायक सीमा त्रिखा ने 25 (20+5) लाख रुपये की ग्रांट दी। लेकिन मालवीय वाटिका के नाम पर दशहरा मैदान में अवैध निर्माण किया गया, जिसे एमसीएफ गिरा चुका है। किस तरह राज्य का मुख्यमंत्री और विधायक अवैध कब्जा करके बनाई गई इमारत को सरकारी ग्रांट दे सकता है। वैसे भी वहां कोई मल्टीपरपज हॉल नहीं बना हुआ है। वहां एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर तमाम आयोजन होते हैं। फरीदाबाद धार्मिक सामाजिक संगठन ने भी अभी तक सरकार और जिला प्रशासन को उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इस 25 लाख रुपये का हिसाब आखिर ये संस्था क्यों नहीं देना चाहती।

विवादों में घिरे फरीदाबाद धार्मिक सामाजिक संगठन को जोगिन्द्र चावला और कंवल खत्री चलाते हैं। यही दोनों श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में भी सक्रिय हैं, जहां अलग तरह का गोरखधंधा चल रहा है। श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री ने 11 लाख रुपये की ग्रांट दी थी। इसकी पड़ताल में तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

कब एक्सरे मशीन आई, कब ग्रांट मिली

मुख्यमंत्री ने 19 जनवरी 2018 को श्रीराम धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल में मशीनरी, उपकरण आदि खरीदने के लिए 11 लाख रुपये की ग्रांट घोषित की। लेकिन इस पैसे की सूचना फरीदाबाद में 20 मार्च 2018 को मिलती है लेकिन पैसे फौरन नहीं आते हैं। इस पैसे को इसी वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 में खर्च करने का निर्देश था। डीसी दफ्तर में इस सरकारी पत्र (1196-बीएपी-1(3)17/1269) की मार्किंग तारीख 31 मार्च 2018 दर्ज है।

हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन को जो दस्तावेज निलम्बित प्रधान कंवल खत्री ने सौंपे हैं उसमें ट्रांसएशिया का बिल है, जिसमें एक मेडिकल उपकरण का आर्डर श्रीराम धर्मार्थ चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा 20 मार्च 2018 को देना दिखाया गया है। इस आर्डर के जरिए कंवल खत्री ने 3 लाख 42 हजार 200 रुपये की खरीदारी दिखाई है। 20 मार्च 2018 की तारीख पर गौर करिए। श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी को सरकारी ग्रांट अभी मिली नहीं है लेकिन जो खरीदारी की गई है, उसका आर्डर 20 मार्च को ही दिया गया है। इस तरह कंवल खत्री और श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी को सपने आ रहे थे कि पैसा आने वाला है और मेडिकल उपकरण खरीद लिया जाए।

सबसे बड़ा फ्रॉड

श्रीराम धर्मार्थ चैरिटेबल सोसाइटी ने किस तरह इस फ्रॉड को अंजाम दिया, अब उसे जानिए। ट्रांसएशिया का जो बिल सोसाइटी और कंवल खत्री ने जमा कराया है, उस पर कॉन्टैक्ट पर्सन (संपर्क व्यक्ति) के रूप में एस.एम. हाशमी का नाम लिखा हुआ है। एस. एम. हाशमी श्रीराम अस्पताल के संस्थापक सदस्य हैं, जिन्हें पूर्व प्रधान रोशनलाल गेरा 2011 में संस्था से निकाल चुके थे और वह मुकदमा अभी भी अदालत में लंबित है। श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल का विवाद जब सामने आया तो सबसे पहले मजदूर मोर्चा ने ही इसके संस्थापक एस.एम. हाशमी को ढूंढ लिया और उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया। एस. एम. हाशमी का कहना है कि 11 लाख की सरकारी ग्रांट से किसी भी तरह के मेडिकल उपकरण खरीदे जाने की जानकारी उनके पास नहीं है। क्योंकि 2011 से संस्था ने कभी उनसे न संपर्क किया और न ही कोई सलाह मांगी। यहां तक अपनी बैठकों में भी संस्थापक सदस्य को नहीं बुलाया। हाशमी ने कहा कि यह उनके नाम पर कंवल खत्री गुट ने बड़ा फ्रॉड किया है। वह वकील से कानूनी सलाह लेने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे।

ट्रांसएशिया ने अपने बिल पर श्रीराम अस्पताल के दो फोन नंबर भी लिखे हैं, दोनों फोन कट चुके हैं और उन पर रिंग करने पर उसकी घंटी बीएसएनएल दफ्तर में जाती है। इस तरह इस फ्रॉड के तार बहुत रहस्यमय ढंग से कई लोगों से जुड़ रहे हैं। जिसमें स्पष्ट तौर पर कंवल खत्री की ही भूमिका नजर आती है।

यहां एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है। श्रीराम धर्मार्थ चैरिटेबल सोसाइटी के महासचिव जितेन्द्र भाटिया का कहना है कि सोसाइटी ने एक्सरे मशीन खरीदने के लिए देना बैंक से नौ लाख रुपये का कर्ज लिया था। जितेन्द्र भाटिया के बयान से भी साबित हो रहा है कि पुराने बिल को सरकारी ग्रांट के पैसे में खर्च दिखा दिया गया है।

हरियाणा सरकार को कंवल खत्री ने दीप बैट्री सर्विस का बिल भी दिया है। इसमें 23050 रुपये का खर्च दिखाया गया है। 7 अप्रैल 2018 को काटे गए इस बिल में जीएसटी का कोई अतापता नहीं है। क्या यह खरीदारी सरकार को बिना जीएसटी दिए की गई। इसी तरह अन्य उपकरणों की खरीद दिखाई गई है और उनके बिल में भी हेराफेरी की गंध आती है। किसी में ई-वे बिल लगा हुआ है, किसी में एकदम से गायब है। इसी तरह के ढेरों अन्य तकनीकी तथ्यों की कसौटी पर कंवल खत्री के उपयोगिता प्रमाणपत्र खरे नहीं उतरते। शहर की ऐसी कई अन्य संस्थाओं को लेकर मजदूर मोर्चा की पड़ताल अभी जारी है।

देखी-सुनी

खबरीलाल

दुष्यंत के दूत के लिए नहीं जुटे कार्यकर्ता

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दूत के रूप में मशहूर हो चुके वीरेन्द्र सिंधु 31 जुलाई को फ़रीदाबाद आए। हिसार निवासी वीरेन्द्र जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट लॉ प्रोफ़ेसर हैं। वीरेन्द्र जेजेपी के आईटी सेल की ज़िम्मेदारी भी संभालते हैं। आप चौंक रहे होंगे कि इतनी छोटी सी पार्टी का आईटी सेल भी है। वीरेन्द्र सिंधु को उम्मीद थी कि जिस तरह दुष्यंत के आने पर फ़रीदाबाद में उनके आगे पीछे भारी भीड़ जुटती है, कुछ वैसी ही भीड़ अब भी जुटेगी। लेकिन उन्हें उस वक्त गहरी निराशा हुई जब मुश्किल से क़रीब 50 नेता/कार्यकर्ता ही जुटे।

सिर्फ़ वीरेन्द्र सिंधु को ही यह ग़लतफ़हमी नहीं है बल्कि जेजेपी के तमाम नेताओं को लग रहा है कि फ़रीदाबाद में जेजेपी का व्यापक जनाधार है। वो दुष्यंत के आने पर होने वाली भीड़ को जेजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ मान बैठे हैं। लेकिन दुष्यंत के आने पर ज़्यादातर लोग अपने काम कराने के लिए दुष्यंत के आगे-पीछे चक्कर लगाते हैं। यह समझ से बाहर है कि आईटी सेल चलाने वाली पार्टियों को

सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा है, उसके मुक़ाबले कार्यकर्ताओं को जोड़ने में विश्वास नहीं करते।

पानी पर पहरा, चोर रोक रहे रास्ता

फ़रीदाबाद में पानी की चोरी रोकने का इंतज़ाम तो हो रहा है लेकिन उसकी गति धीमी है। सेक्टर 25. में रैनीवेल बूस्टर स्टेशन की रखवाली के लिए पुलिस तीन शिफ़्टों में ड्यूटी कर रही है लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वॉर्ड 7 की पार्षद ललिता यादव ने उनके वॉर्ड में पड़ने वाले बूस्टर पंप से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस तैनात करने की माँग की है। यानी यह माँग बता रही है कि पानी की चोरी का मामला गंभीर रूप ले चुका है। इसका समाधान है कि बूस्टर पंपों पर लगे वॉल्व पर बोल्ट लगा दिए जाएँ। ताकि कोई सीधे पानी की चोरी नहीं कर सके। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने जब यह निर्देश एक्सईएन ओ.पी. कर्दम को दिया तो वह तमाम बहाने बनाने लगा। उसने कि वॉल्व पर बोल्ट लगाने में 72 घंटे लगेंगे। यानी एक्सईएन की पूरी कोशिश है कि बूस्टर पंपों से पानी की चोरी होती रहे और उन्हें हिस्सा मिलता रहे। स्पष्ट है कि फ़रीदाबाद में एमसीएफ के अधिकारी जल माफिया से मिलकर चोरी करा रहे हैं। जिसमें एमसीएफ के इंजीनियर विंग के अफ़सरों और कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका है। इनमें चीफ़ इंजीनियर के बाद सबसे कुख्यात कर्दम बंधु हैं।

जिसको गाली दी, उसे गले लगाया

पूर्व विधायक स्व. कुंदन लाल भाटिया के बेटे जगदीश भाटिया कब पाला बदल लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुंदनलाल भाटिया अपने पीछे जो राजनीतिक और सामाजिक रसूख़ की जो विरासत छोड़कर गए थे, उनके बेटे उसे ढंग से निभा नहीं पाए। कुंदनलाल भाटिया तमाम मुद्दों पर स्पष्ट स्टैंड लेते थे लेकिन जगदीश भाटिया में वो बात नहीं है। जगदीश भाटिया वैष्णो देवी मंदिर की कमेटी के प्रधान होने के अलावा व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब इन्हीं जगदीश भाटिया ने व्यापारियों की जायज़ माँगों को रखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर और उनकी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तक की मुर्दाबाद हुई थी। 31 जुलाई को गूजर वैष्णो देवी मंदिर में जगदीश भाटिया के निमंत्रण पर वैक्सीन कैंप का उद्घाटन करने जा पहुँचे। कोरोना भूलकर दोनों जमकर गले मिले। शहर के पंजाबियों ने इस मौक़े पर एक पुराना वीडियो जारी कर याद दिलाया कि कैसे जगदीश भाटिया खट्टर सरकार मुर्दाबाद कर चुके हैं। लोगों ने दशहरा में धार्मिक मंच पर हुए विवाद में कृष्णपाल गूजर की भूमिका की याद दिलाई। जिस जगदीश भाटिया पर कुंदनलाल भाटिया की परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी थी वो विधायक सीमा त्रिखा के दरबार में हाज़िरी लगा रहा है। जगदीश भाटिया को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीमा त्रिखा का सहारा लेना पड़ रहा है। हाय रे एनआईटी तेरी किस्मत...

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06